world, salt plays the most essential part in human body, whereas refined salt is essential for manufacturing units. As you are aware, Sir, an unprecedented, abnormal increase in railway freight has been made effective since 6.3.2012. The revised rates are on the exceptionally higher side and are detrimental to the interests of salt industry in Gujarat. They are adversely affected due to enhanced freight.

It is seen from the freight rates table that initially, per tonne charges for various classes are fixed for the distance of 25 and 50 kilometres. But, from 1000 to 1500 kilometres, it is fixed at 100 kilometres. In the subsequent block/slab, the distance is 250 kilometres up to 2000 kilometres and 500 kilometres for 2500 kilometres onwards.

It is our humble request that some reduction may kindly be made in the freight structure. Gujarat's salt manufacturers, who are meeting the country's major requirement of edible salt, are worst hit by this rise. The consumption of the refined salt has increased manifold. Even the State Government supply refined iodised salt to the poorest of the poor under the Public Distribution System and salt has virtually become an essential commodity.

As Railways grant concession in freight in respect of ordinary iodised salt, we request you to grant similar concession to refined salt also so that the industry can survive.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, Shrimati Renubala Pradhan, not here. Now, Shri Sukhendu Sekhar Roy.

Demand to take measures to ensure proper implementation of national training policy

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal) : Sir, I would like to raise a very important issue before this august House.

The Training Division of the Department of Personnel and Training is responsible for Trainers' Development Programmes in the country. There are several instances of irregularities noticed in the implementation of this policy. The Training Division insists that a Certified Trainer, who is presently posted in a Ministry or Department of Central Government or State Government, should conduct a training programme as and when deployed by them. However, instead of taking action against the employers of Certified Trainers for not relieving these trainers to conduct deployed courses, it is taking action against these trainers.

Recently, the Training Division has withdrawn certification of five national resource persons who created an advanced level training package in collaboration with the University of Manchester, at the cost of the Government exchequer in which the employers of these trainers did not relieve them as and when deployed by the Training Division. Had these trainers' services been utilised, some more trainers could have been deployed by them. There is no definite strategy adopted for other training

[SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY]

packages. Training Division is indulging in indiscipline and demoralising the trainers' community as a whole. There are other irregularities in allocating training programmes. There is no policy of deployment of trainers in various parts of the country.

Therefore, I would request the Government to initiate measures to remove disparity in implementation of the trainers' development policy. The Government may immediately review the policy of trainers' development and take suitable action to implement training for all.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of answer given on 7th May, 2012, to Starred Question No. 423 regarding 'Promotion of entrepreneurship and self-employment among minorities

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : सर, कल मेरे सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने एक डिटेल्ड खत मुझको भेजा और मैं उसको देखकर यह सोचने लगा कि इस पर कैसे रिएक्ट करूं। मैं बार-बार यह कहता हूं कि माइनॉरटी मिनिस्ट्री सच्चर कमेटी का हवाला देती है कि सच्चर कमेटी की रिक्मेंडेशंस के ऊपर हमने माइनॉरटी के लिए यह-यह किया है। सच्चर कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि इस देश में मुसलमानों की क्या दुर्दशा है, यह पता चल सके। सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि मुसलमान इस देश में दलितों के बराबर नीचे पहुंच गया है और उसके लिए कोई-न-कोई चाराहगो करना होगा। हमारी सरकार ने उसको कहा कि हम इम्पिलमेंट कर रहे हैं और इसके लिए एक माइनॉरटी मिनिस्ट्री बनाई है। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के हमेशा शुक्रगुज़ार रहेंगे।

कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाने के बाद कहा कि हम 15 सूत्री कार्यक्रम ला रहे हैं जिसमें मुसलमानों को including other minorities, बहुत फायदे होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि चूंकि माइनॉरिटीज में, मुस्लिम मायनॉरिटी सब से पीछे है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हें दिया जाएगा, लेकिन इस खत के आने के बाद और दसियों खुतूत और information के बाद, जो मैंने और मेरे साथियों ने collect की है, उससे यह पता चलता है कि मुसलमान को कुछ भी नहीं मिला है। सर, मुसलमानों को bifurcation के लिए हमेशा कहा गया कि आप कुछ दीजिए। मुझे मंत्री महोदय के पत्र में सबसे बेहतर चीज यह लगी और उसमें यह कहा गया कि, हमने मैट्रिक, प्रि-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी हैं। इसमें यह क्लेम किया गया है कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों को हमने स्कॉलरशिप दी हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह फिगर कैसे बन गयी? जब आप example के तौर पर एक तीसरे दर्जे के बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं, वह पास कर के चौथे दर्जे में भी जाता है और वही बच्चा पांचवे दर्जे में भी जाता है, तो इन तीन सालों की फिगर को जोड़कर, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं कि 1 करोड़ 40 लाख की जो फिगर आपने दी है, वह सिर्फ उन बच्चों की है जिन्हें मिलाकर आप हर साल स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उन्हें club करके आपने दी है या 1 करोड़ 40 लाख अलग बच्चों को स्कॉलरशिप दी है? यही एक स्कीम है और इसमें आपने लिखा भी है कि 70 परसेंट मुसलमानों को दी गयी है। यह ठीक बात है और 70 परसेंट उनका शेयर बनता है। यह बिल्कुल acceptable है। फिर यह कहा गया कि हम और स्कीम लाए हैं जिसके लिए हमने 90 जिले तय किए हैं और इनमें 3,780 करोड़ रुपए डवलमेंट के लिए दिए हैं। आपने माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा खजाना खोल दिया! जहां लाखों-लाख का बजट हो, आपने कहा कि हमने 3,780 करोड़ रुपए दे दिए हैं और उसमें से भी 840 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। यह हमारी हैसियत है। यह कहा गया कि ये वे जिले